पेट्रोल, डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती

नई दरें 1 जून से लागू; घरेलू ईंधन उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा कोई असर

नई दिल्ली, 31 मई केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती कर दी है. सरकार की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार नई दरें 1 जून से प्रभावी होंगी. हालांकि, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल पर लागू मौजूदा उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे देश के भीतर ईंधन खरीदने वाले उपभोक्ताओं पर इस फैसले का प्रत्यक्ष असर नहीं पड़ेगा.

नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल के निर्यात पर ड्यूटी 1.5 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर 13.5 रुपये प्रति लीटर तथा विमानन ईंधन पर 9.5 रुपये प्रति लीटर निर्धारित की गई है. सरकार द्वारा इन दरों की नियमित समीक्षा अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के आधार पर की जाती है. आमतौर पर हर 15 दिन में इन शुल्कों का पुनरीक्षण किया जाता है ताकि घरेलू आपूर्ति और निर्यात के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके.

एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती से तेल रिफाइनिंग कंपनियों को राहत मिलेगी और वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत होगी. वहीं, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तत्काल किसी बदलाव की संभावना नहीं है क्योंकि घरेलू बिक्री पर लगने वाली कर व्यवस्था यथावत रखी गई है.

> सरकार का कहना है कि निर्यात शुल्क में समय-समय पर संशोधन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और रिफाइनरियों के मुनाफे को संतुलित रखना है. एक्सपोर्ट ड्यूटी एक ऐसा कर है जो विदेशों में बेचे जाने वाले उत्पादों पर लगाया जाता है, जबकि एविएशन टर्बाइन ईंधन वह विशेष केरोसिन आधारित ईंधन है जिसका उपयोग विमानों के टर्बाइन इंजनों को संचालित करने में किया जाता है.

चावल में साप्ताहिक गिरावट, दालों खाद्य तेलों में घट-बढ़

नयी दिल्ली, 31 मई. घरेलू थोक जिंस बाजारों में बीते सप्ताह चावल का औसत भाव गिर गया. गेहूं और चीनी के भाव लगभग अपरिवर्तित रहे जबकि खाद्य तेलों और दालों में उतार-चढ़ाव देखा गया. सप्ताह के दौरान चावल की औसत कीमत 12 रुपये टूटकर सप्ताहांत पर 3,837 रुपये प्रति क्विंटल रह गयी. गेहूं 2,794 रुपये प्रति क्विंटल पर लगभग स्थिर रहा. आटे का भाव छह रुपये बढ़कर 3,278 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया. सप्ताह के दौरान मसूर दाल की औसत कीमत 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गयी. चना दाल 21 रुपये और 13 तुअर दाल 13 रुपये प्रति क्विंटल महंगी हुई. उड़द दाल 29 रुपये और मूंग दाल चार रुपये प्रति क्विंटल सस्ती हुई.

महंगाई कमजोर मानसून में अर्थव्यवस्था मजबूत

सेवा निर्यात, विदेशी मुद्रा भंडार और स्थिर श्रम बाजार ने बनाए आर्थिक ढांचे

ऊर्जा कीमतें और कमजोर मानसून चिंताएं बढ़ा रहे हैं

नई दिल्ली, 31 मई वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने 'सतर्क मजबूती' का परिचय दिया है. वित्त मंत्रालय की मई 2026 की मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में बताया गया कि महंगाई और कमजोर मानसून की दोहरी चुनौती के बावजूद देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है.

भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में कई सकारात्मक संकेतों के बावजूद चुनौतियों का सामना कर रही है. रिपोर्ट के अनुसार, सेवा निर्यात में मजबूती, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और स्थिर श्रम बाजार देश की आर्थिक धारा को बनाए रखने में सहायक हैं. ये कारक यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू दबावों के बावजूद आर्थिक ढांचा डगमगाए नहीं.

हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी, भारतीय रुपये में कमजोरी और कंपनियों की उत्पादन लागत में इजाफा सरकार की सतर्कता बढ़ा रहे हैं. इसके अलावा, इस वर्ष सामान्य से कम होने की संभावना वाले मानसून ने खाद्य उत्पादन पर नकारात्मक असर डालने की आशंका पैदा कर दी है. वित्त मंत्रालय इन सभी जोखिमों पर लगातार नजर रख रहा है और मौद्रिक, राजकोषीय एवं संरचनात्मक नीतियों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है.

महंगाई पर बढ़ता दबाव- रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि इस समय खुदरा महंगाई और थोक कीमतों के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है. इसका अर्थ है कि उत्पादन स्तर पर लागत का दबाव काफी अधिक है.

व्यापार और निवेश में मजबूती

इन तमाम चुनौतियों के बीच भारत ने विदेशी व्यापार में शानदार प्रदर्शन किया है. अप्रैल 2026 में देश के कुल निर्यात में जबरदस्त उछाल देखा गया. वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में भारत का कुल निर्यात 80.8 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 13.6 प्रतिशत अधिक है. वहीं, व्यापार घाटा 7.8 अरब डॉलर तक घट गया, जो पिछले साल अप्रैल में 11.2 अरब डॉलर था. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी भारत ने रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है.

सीनियर सिटीजंस के लिए सही आईटीआर फॉर्म चुनना जरूरी

गलत फॉर्म भरने पर इंकम टैक्स नोटिस का खतरा

75+ उम्र वालों को कुछ शर्तों पर राहत

नई दिल्ली, 31 मई 2026 आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स को सक्रिय करना शुरू कर दिया है. इस बीच सीनियर सिटीजंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपनी आय के अनुसार सही ड्डञ्जक्रफॉर्म का चयन करें, क्योंकि गलत फॉर्म भरने पर न केवल रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है, बल्कि इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस भी जारी किया जा सकता है.

विभाग के अनुसार आईटीआर फॉर्म का चयन उम्र के आधार पर नहीं बल्कि आय के स्रोत पर निर्भर करता है. 15 मई से आईटीआर-1 और आईटीआर-4 पहले ही पोर्टल पर उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जबकि 27 मई से आईटीआर-2 भी ऑनलाइन भरने के लिए सक्रिय कर दिया गया है. आईटीआर-3 फॉर्म अभी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है.

आईटीआर-1 उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयुक्त है जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी आय पेंशन, एक या दो मकानों से किराया तथा बैंक एफडी या बचत खाते के ब्याज तक सीमित है. वहीं, यदि किसी सीनियर सिटीजंस को शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या संपत्ति की बिक्री से पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन्स) होता है या उनके पास दो से अधिक संपत्तियां हैं, तो उन्हें आईटीआर-2 फॉर्म भरना अनिवार्य है.आईटीआर-4 उन लोगों के लिए है जो अनुमानित कराधान योजना (प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम) के तहत व्यवसाय या पेशे से आय अर्जित करते हैं.

टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि गलत फॉर्म का चयन करना एक सामान्य गलती है, लेकिन इसका प्रभाव गंभीर हो सकता है. इससे रिफंड में देरी, अतिरिक्त पूछताछ और टैक्स नोटिस जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं.

इसके अलावा, आयकर अधिनियम के तहत 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआरफाइलिंग से छूट दी गई है, जिनकी आय केवल पेंशन और उसी बैंक से मिलने वाले ब्याज तक सीमित है, जहां उनका पेंशन खाता है.

पतंजलि फूड्स की आय रिकॉर्ड स्तर पर

मुंबई, 31 मई दैनिक उपभोग, पर्सनल केयर और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का कारोबार करने वाली प्रमुख कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने खरेलू उपभोक्ता मांग के मजबूत रुझानों के बल पर 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष 2025-26 में की चौथी तिमाही और पूरे वित्त वर्ष में परिचालन से अब तक का सबसे अधिक राजस्व दर्ज किया है.

पूरे वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए कंपनी का परिचालन राजस्व सालाना आधार पर 18.99 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रिकार्ड 40,169.58 करोड़ रुपये रहा. इस दौरान कुल परिचालन लाभ (असाधारण मदों को छोड़कर) 1,931.52 करोड़ रुपये रहा रहा.

कंपनी ने शनिवार शाम जारी वार्षिक और तिमाही वित्तीय रिपोर्ट में कहा कि गत 31 मार्च को समाप्त तिमाही में उसका परिचालन राजस्व सालाना आधार पर 17.28 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 11,155.60 करोड़ रुपये रहा. तिमाही-दर-तिमाही आधार पर राजस्व में 6.41 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. इसी तिमाही में त्वरित उपभोक्ता (एफएमसीजी खंड) में कंपनी की परिचालन आय 2,890.46 करोड़ रुपये रही.

चौथी तिमाही में खाद्य तेल कारोबार में आय सालाना आधार पर 23.28 प्रतिशत और तिमाही-दर-तिमाही आधार पर 13.47 प्रतिशत बढ़कर 8,324.11 करोड़ रुपये हो गयी. कंपनी ने बिक्री की मात्रा में बढ़ोतरी को राजस्व वृद्धि का मुख्य आधार बताया. मार्च 2026 में समाप्त तिमाही में कंपनी ने सकल लाभ मार्जिन 12.47 रहा, परिचालन लाभ का मार्जिन 4.48 प्रतिशत (असाधारण मदों को छोड़कर), और शुद्ध लाभ मार्जिन 2.10 प्रतिशत दर्ज किया.

मार्च 2026 तक पातंजलि का पाम ऑयल बागान का कुल रकबा 1,10,722 लाख हेक्टेयर था.

कंपनी की विज्ञप्ति में कहा गया है कि 21 अप्रैल 2026 को हुई अपनी बैठक में उसके निदेशक मंडल ने 2025-26 के लिए, 2 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 1.75 रुपये का दूसरा अंतरिम लाभांश घोषित किया है.

> पतंजलि फूड्स लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव अस्थाना ने कहा, ''मार्च तिमाही में, घरेलू मांग की अच्छी गति बनी रही और परिचालन संरचनात्मक रूप से मजबूत बना रहा. जीएसटी से जुड़ी चीजों के सामान्य होने के बाद, बिक्री चैनलों से माल की तेजी से निकासी ने खपत के रुझानों को सहारा दिया. ग्रामीण इलाकों में मांग की मजबूती बनी रही. शहरी खपत में भी तेजी देखने को मिली और इसमें हाल ही में मिले कर लाभों और वैकल्पिक वितरण चैनलों के इस्तेमाल में आसानी का योगदान रहा.

जैव विविधता प्राधिकरण को 21.26 करोड़ प्राप्त

नयी दिल्ली, 31 मई राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) को वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जैव संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग की सुविधा और लाभ साझाकरण व्यवस्था के अंतर्गत 21.26 करोड़ रुपये प्राप्त हुए.

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार यह राशि अनुसंधान, वाणिज्यिक उपयोग, बौद्धिक संपदा अधिकार, जैव सर्वेक्षण और जैविक संसाधनों के जैव उपयोग के लिए दी गई स्वीकृतियों से प्राप्त हुई है और देश के जैव विविधता शासन ढांचे में उद्योग की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है.

एबीएस की व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जैविक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभ स्थानीय समुदायों, जैव विविधता प्रबंधन समितियों, किसानों और पारंपरिक ज्ञान धारकों के साथ निष्पक्ष और समान रूप से साझा किए जाएं. इससे प्राप्त धनराशि जैव विविधता संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और जमीनी स्तर पर आजीविका संवर्धन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है.

विज्ञप्ति के अनुसार 31 मार्च 2026 को समाप्त पिछले वित्त वर्ष में प्राधिकरण की इन प्राप्तियों में बीज क्षेत्र का योगदान 11.75 करोड़ रुपये के साथ सबसे अधिक रहा.

कपास आयात पर छूट कच्चा माल सस्ता

नयी दिल्ली, 31 मई. घरेलू कपड़ा उद्योग के लिए कपास की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से, केंद्र ने कपास के आयात पर लगने वाले सभी सीमा शुल्कों से अस्थायी रूप से छूट दे दी है. शनिवार को जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार यह छूट 1 जून, 2026 से 30 अक्टूबर, 2026 तक लागू रहेगी. सरकार का कहना है कि इस अस्थायी शुल्क छूट से कपड़ा और परिधान क्षेत्र में कच्चे माल की लागत कम होने की उम्मीद है, जिससे निर्माताओं और उपभोक्ताओं को लक्षित राहत मिलेगी.

तथ्यपूर्ण तैयारी से आने की अपील, शीघ्र न्याय

नयी दिल्ली, 31 मई माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के अध्यक्ष, माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संजय कुमार मिश्रा ने अपने फोरम के समक्ष अपील के लिए आने वालों को पूरी तैयारी, पेशेवर कुशलता और तथ्यों पर पूरी पकड़ के साथ आने की अपील की है.

पीएचडी वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की ओर से यहां जीएसटीएटी एक राष्ट्रीय सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए श्रीमद्भगवद्गीता के महावाक्य 'योग: कर्मसु कौशलम्' का उल्लेख करते हुए कहा कि वकीलों को मुकदमों को पूरी लगन और उत्कृष्टता के साथ लड़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की सफलता समय पर, प्रभावी और ठोस न्याय देने में निहित है. यह फोरम जीएसटी लागू होने के सात साल बाद स्थापित हो पाया लेकिन अब यह वास्तविकता बन गया है.

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि ट्रिब्यूनल का मार्गदर्शक सिद्धांत—'एपीलेट देवोभव (अपीलीय देवो भव)'—पर ज़ोर दिया, जो यह सुनिश्चित करता है कि अपील करने वालों के साथ सम्मान से पेश आया जाए, और उनकी अपीलें निष्पक्ष और बिना देरी के बावजूद, ट्रिब्यूनल से करदाताओं को विवादों को सुलझाने का एक किफायती तरीका मिलने की उम्मीद है. उन्होंने आगे कहा कि हालांकि जीएसटी के तहत अब तक लाखों आदेश पारित किए जा चुके हैं, फिर भी जीएसटीएटी पोर्टल पर काफी हलचल देखने को मिली है.

जीएसटी के महत्व पर प्रकाश डाला

सत्र की शुरुआत करते हुए, पीएचडी उद्योग मंडल की अप्रत्यक्ष कर समिति के अध्यक्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक बत्रा ने जीएसटी के तहत तथ्यों का पता लगाने वाली अंतिम संस्था के रूप में जीएसटीएटी के महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि इसके गठन में

भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत सतर्क रहना जरूरी

नयी दिल्ली, 31 मई . वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को विभिन्न संकेतकों के हवाले से भारतीय अर्थव्यवस्था के परिदृश्य को मजबूत बताया लेकिन साथ ही पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर सतर्कता की आवश्यकता पर भी जोर दिया. वित्त मंत्रालय की शनिवार को जारी मासिक रिपोर्ट के अनुसार, सेवा क्षेत्र का निर्यात मजबूत है, देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार का पर्याप्त भंडार है और बाजार में स्थिरता है जो एक मजबूत आधार प्रदान करता है. रिपोर्ट में कहा गया है, 'निकट भविष्य में देश का (आर्थिक) परिदृश्य मजबूत है, लेकिन सतर्कता की जरूरत है.'

समाचार विशेष

उपचुनाव में भाजपा को कैसे हराएंगे पीके?

पटना. प्रशांत किशोर का दावा है कि उनकी पार्टी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मजबूती से लड़ेगी और भाजपा को उसके गढ़ में घुस कर हराएगी. पिछले चुनाव में जिस पार्टी की 238 में से 236 सीटों पर जमानत जब्त हो गयी हो, क्या उसके नेता के इस दावे को गंभीरता से लेना चाहिए? बिहार चुनाव में उनके सभी दावे पानी के बुलबुले साबित हुए. इसके बाद भी वे भाजपा को उसके गढ़ में घुस कर हराने का दावा कर रहे हैं. क्या यह संभव है? या फिर चखाया-पीया कुछ नहीं और ग्लास फोड़ा बारह आने काज मुहावरा चरितार्थ कर रहे हैं?

बांकीपुर सीट 2010 में अस्तित्व में आयी. अब तक हुए सभी चार चुनावों में नितिन नवीन ने शानदार जीत दर्ज की. पहली बार 78 हजार से अधिक वोटों मिले. 2015 में लालू यादव और नीतीश कुमार की संयुक्त ताकत भी नितिन नवीन का कुछ नहीं बिगाड़ पायी. बल्कि प्रतिक्रिया में नितिन नवीन और ज्यादा वोट (86 हजार से अधिक) मिले. यानी यहां लालू-नीतीश का कास्ट फैक्टर भी प्रभावी नहीं. 2020 में वे 83 हजार वोट मिले. 2025 में तो सारे रिकॉर्ड टूट गये और वोटों का आंकड़ा 98 हजार तक पहुंच गया. यानी राजनीतिक परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही हों, भाजपा के वोट यहां बढ़ते रहे हैं. बांकीपुर विधानसभा सीट पहले पटना पश्चिम के नाम से जानी जाती थी. तब से इस सीट पर भाजपा का दबदबा है.

जमानत जब्ती का रिकॉर्ड बना था जन सुराज पार्टी का

लालू और शत्रुघ्न भी यहां फीके पड़ गए- ऐसा नहीं है कि भाजपा को इस सीट पर हराने के लिए विरोधी दलों ने पैंतरे नहीं आजमाये. हर एक चाल चल कर देख ली. लेकिन भाजपा को हरा नहीं पाए. इस सीट पर कायस्थ जाति के मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है. कायस्थ समाज भाजपा का समर्पित वोटर माना जाता है. अगर किसी दूसरे दल से कायस्थ उम्मीदवार खड़ा हो भी जाए, तब भी वे भाजपा को ही वोट करते हैं. इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए 2010 में लालू यादव ने अपने निजी सचिव रहे विनोद कुमार श्रीवास्तव को बांकीपुर से उम्मीदवार बनाया था.

पीके ने दिया था भूमिहार ब्राह्मण को टिकट, करारी हार

2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट पर अपनी हैसियत देख चुके हैं. वंदना कुमारी ने जन सुराज पार्टी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ा था. उन्हें केवल 7 हजार 717 वोट मिले थे. वे तीसरे स्थान पर रहीं थीं. इस सीट पर नितिन नवीन ने राजद की रेखा कुमारी को करीब 41 हजार वोटों के बड़े अंतर से हराया था. प्रशांत किशोर ने इस सीट एक भूमिहार ब्राह्मण (वंदना कुमारी) को टिकट दिया था. बांकीपुर में कायस्थ के बाद भूमिहार ब्राह्मण और ब्राह्मण वोटर भी असरदार माने जाते हैं. लेकिन यह जाति समूह भी भाजपा का कट्टर समर्थक है.

राज्यसभा चुनाव जीतने को जुटी भाजपा

सत्ताधारी विधायकों से समर्थन की उम्मीद

रांची. राज्यसभा की दो सीटों पर होने वाले चुनाव में एक सीट की दावेदारी कर रही भाजपा में इन दिनों मंथन का दौर जारी है. पार्टी की ओर से प्रत्याशी कौन होगा इससे ज्यादा पार्टी कम पर रहे वोटों के आंकड़ों को पूरा करने में जुटी है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू सहित अन्य नेता जल्द ही एनडीए के सभी सहयोगी दल जदयू, लोजपा रामविलास और आजसू सुप्रीमो से मुलाकात करेंगे. राज्यसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने की पहल करने पर चर्चा होगी.

इधर राज्यसभा चुनाव को ध्यान में रखकर भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन का झारखंड दौरा जून के पहले सप्ताह में होने की संभावना है. भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन इस दौरान पार्टी के कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे और रणनीति को अंतिम मुकाम देंगे.

भाजपा नेता दीनदयाल वर्णवाल कहते हैं कि प्रदेश नेतृत्व के द्वारा पार्टी प्रत्याशी खड़ा करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि हमारे पास भले ही तीन-चार वोट कम पड़ रहे हो, लेकिन हमें उम्मीद है कि केंद्र की मोदी सरकार के विकास और विश्व में भारत की पहचान को ध्यान में रखकर विधायक न केवल मतदान करेंगे, बल्कि हमारे प्रत्याशी का सहयोग भी करेंगे. उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि सत्तारुढ़ दल के अंदर समन्वय का अभाव है जिसका लाभ राज्यसभा चुनाव में भाजपा को मिलने की उम्मीद है.

ऑपरेशन केरल शुरू हो गया

तिरुवनंतपुरम. भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन केरल शुरू हो गया है. उसको लग रहा है कि जब तक केरल में त्रिकोणात्मक लड़ाई होगी और लेफ्ट की मौजूदगी बनी रहेगी तब तक भाजपा के लिए स्कोप नहीं बनेगा. दो चुनावों में उसने देख लिया है कि उसका वोट 12 फीसदी से ऊपर नहीं जा रहा है. लोकसभा चुनाव में जरूर थोड़ा ज्यादा वोट मिला लेकिन विधानसभा में केरल के लोग अब भी कांग्रेस और सीपीएम गठबंधन के बीच रिवॉल्विंग डोर पोलिटिक्स के साथ हैं.

भाजपा को यह भी पता है कि केरल के 55 फीसदी हिंदू मतदाताओं में से ज्यादातर का रूझान लेफ्ट यानी सीपीएम गठबंधन की ओर है.

तभी ऑपरेशन केरल के तहत सीपीएम को निशाना बनाया गया है. राज्य में सीपीएम के सबसे बड़े नेता और दो बार लगातार मुख्यमंत्री रहे पिनरायी विजयन के यहां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के छापे से इसका संकेत मिलता है. यह मामला विजयन की बेटी की कंपनी से जुड़ा है.

> विजयन पर यह आरोप पहले लगा था कि उन्होंने अपनी बेटी वीणा के पति को राज्य सरकार में मंत्री बनाया. फिर वीणा की कंपनी को बिना काम कराए भुगतान का मामला आया. अगर वंशवाद और भ्रष्टाचार के आरोप में लेफ्ट कमजोर होता है तो अपने आप भाजपा के लिए जगह बनेगी. ध्यान रहे लेफ्ट नेताओं खास कर विजयन के हिंदू वोटों पर ज्यादा फोकस करने का नुकसान लेफ्ट को हुआ. ईसाई और मुस्लिम वोट कांग्रेस की ओर गोलबंद हुआ. अगर हिंदू वोट लेफ्ट से टूट कर भाजपा की ओर आता है तो भाजपा और कांग्रेस का आमने सामने का मुकाबला बनेगा, जिसमें भाजपा को जीतने की संभावना दिख रही है.

विशेष | **कैंट विधानसभा सीट भाजपा का रहा मजबूत किला**

भाजपा विरासत को देगी तवज्जो या नया चेहरा

देहरादून. राजधानी की कैंट विधानसभा वर्ष 1985 से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला रही है. बावजूद इसके यहां कपूर परिवार के अलावा कई दावेदार हैं जो तैयारी में जुटे हैं. अब देखना ये है कि वर्तमान विधायक सविता कपूर की उम्र को देखते हुए भाजपा राजनीतिक विरासत को तवज्जो देगी या नया चेहरा लाएगी

उत्तराखंड गठन से पहले यूपी के समय देहराखास सीट पर 1985 में हरबंस कपूर जीतकर विधायक बने थे. इसके बाद ये सिलसिला उनके निधन के बाद भी अनवरत जारी है. 2017 के चुनाव में स्व. हरबंस कपूर ने 22.89 प्रतिशत वोटों के अंतर से अपना आखिरी चुनाव जीता था. उनके निधन के बाद 2022 के चुनाव में भाजपा ने उनकी पत्नी सविता कपूर पर भरोसा जताया. सविता कपूर ने अपना चुनाव पति से भी ज्यादा 27.36 प्रतिशत वोटों के अंतर से जीता था.

अब उनकी उम्र बढ़ने के साथ ही कैंट विधानसभा भाजपा नेताओं के लिए हॉट सीट है. एक ओर जहां लंबे समय से यहां भाजपा प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान चुनाव की तैयारी में जुटे हैं तो वहीं भाजपा नेता विनय गोयल, जोगेंद्र पुंडीर, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल भी जोर आजमाइश कर रहे हैं. अब देखना ये होगा कि अपने मजबूत किले में पार्टी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए स्व. हरबंस कपूर के पुत्र अमित कपूर पर भरोसा करेगी या फिर इनमें से किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी. 2022 के चुनाव में यहां 77,113 मतदाता थे. इस सीट पर 56.89 प्रतिशत मतदान हुआ था. भाजपा की प्रत्याशी सविता कपूर ने 45,492 मत हासिल किए थे. उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी सूर्यकांत धस्माना ने 24,554 मत हासिल किए थे.

पूर्व सैनिक, गोरखा, पंजाबी वर्ग का है प्रभाव

जातीय और सामाजिक नजरिए से देखें तो कैंट विस क्षेत्र में सेना के मौजूदा जवानों, उनके परिवारों और भारी संख्या में पूर्व सैनिकों के वोट हैं. गढ़ी कैंट, डाकरा, और गढ़ी क्षेत्र के आस-पास गोरखा समुदाय की अच्छी-खासी आबादी है. राजधानी का हिस्सा होने के चलते उत्तराखंड के पर्वतीय मूल के मतदाताओं(विशेषकर ठाकुर और ब्राह्मण) की भी यहां खासी संख्या है.